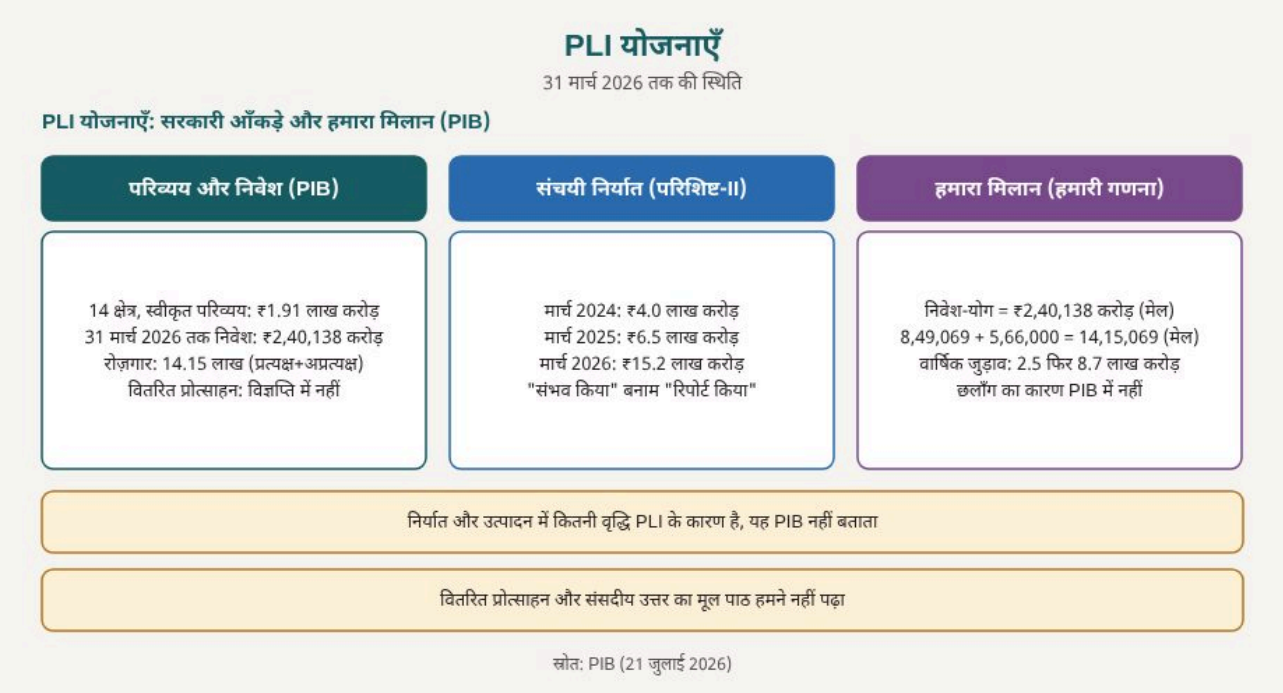
PLI योजनाएँ: निर्यात और निवेश के सरकारी आँकड़े



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

अर्थव्यवस्था / उद्योग नीति | समाचार संदर्भ: लोकसभा में PLI योजनाओं का लिखित उत्तर, 21 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ निर्धारित आधार-वर्ष से अधिक बिक्री पर नकद प्रोत्साहन देती हैं, ताकि घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात बढ़ें। PIB (21 जुलाई 2026) के अनुसार सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹1.91 लाख करोड़ के स्वीकृत परिव्यय पर ये योजनाएँ शुरू की हैं। समग्र समन्वय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) करता है, जबकि कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालय करते हैं।

14 नवंबर 2026 का अपडेट: PIB समीक्षा – जून 2026 तक निवेश 2.58 लाख करोड़, उत्पादन 23.79 लाख करोड़ रुपये पार

प्रेस सूचना ब्यूरो की 13 नवंबर 2026 की समीक्षा के अनुसार जून 2026 तक 14 क्षेत्रों में **791 आवेदन स्वीकृत** हुए; वास्तविक निवेश **2.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक** (31 मार्च 2026 के 2.40 लाख करोड़ के आंकड़े से आगे), उत्पादन/बिक्री **23.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक**, निर्यात में **15.53 लाख करोड़ रुपये** की वृद्धि और **14.57 लाख रोजगार** दर्ज हुए। संचयी प्रोत्साहन-संवितरण **36,754 करोड़ रुपये** रहा।

क्षेत्रवार: इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा लाभार्थी (LSEM में निवेश लक्ष्य का ~3 गुना); **देश में उपयोग होने वाले 99.2% फोन घरेलू निर्मित**, मोबाइल आयात ~77% घटा; 191 बल्क ड्रग्स का पहली बार घरेलू निर्माण; IT हार्डवेयर निर्यात में 77.2% औसत वार्षिक वृद्धि (2021-2025)।

खबरों में क्यों

PIB के अनुसार वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 31 मार्च 2026 तक PLI योजनाओं के तहत ₹2.40 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश और 14.15 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष

और अप्रत्यक्ष) रोज़गार हुआ, और योजनाओं ने शुरू होने से अब तक ₹15.2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात "संभव" किया।

मुख्य अवधारणा: "रिपोर्ट किया गया" बनाम "संभव किया गया"

PIB का पाठ कहता है कि योजनाओं ने ₹15.2 लाख करोड़ का निर्यात "enabled" किया, जबकि उसी विज्ञप्ति का परिशिष्ट-II इसे "योजनाओं के तहत रिपोर्ट किया गया संचयी निर्यात" कहता है। यानी यह लाभार्थी कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई राशि है; विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि इसमें से कितना PLI के कारण हुआ और कितना वैसे भी होता।

मुख्य तथ्य और आंकड़े

मुख्य आँकड़े (PIB)	**14 क्षेत्र, परिव्यय ₹1.91 लाख करोड़। 31 मार्च 2026 तक निवेश ₹2,40,138 करोड़ (परिशिष्ट-I का योग)। संचयी निर्यात: मार्च 2024 तक ₹4.0 लाख करोड़, मार्च 2025 तक ₹6.5 लाख करोड़, मार्च 2026 तक ₹15.2 लाख करोड़।**
क्षेत्र-वार दावे (PIB)	बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल उत्पादन लगभग 2.4 गुना, मोबाइल आयात में लगभग 77 प्रतिशत की कमी और देश में प्रयुक्त लगभग 99.2 प्रतिशत फ़ोन घरेलू स्तर पर बने। फ़ार्मा में ₹3.64 लाख करोड़ से अधिक की संचयी बिक्री और 1,931 उत्पादों का घरेलू निर्माण, जिनमें 191 बल्क ड्रग पहली बार। बल्क ड्रग में 26 API पर लगभग 55,000 टन क्षमता। चिकित्सा उपकरणों में 22 आवेदकों ने परिचालन शुरू किया और 55 उपकरण चालू। श्वेत वस्तुओं में कंप्रेसर क्षमता 2021 में 10 लाख इकाई से 2025-26 में 1 करोड़ इकाई।
निवेश का क्षेत्र-वार बँटवारा (परिशिष्ट-I)	सबसे आगे: सौर PV मॉड्यूल ₹64,873 करोड़, फ़ार्मा ₹45,158 करोड़, ऑटोमोबाइल और ऑटो-पुर्ज़े ₹44,326 करोड़, विशेष इस्पात ₹23,896 करोड़, बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स ₹20,580 करोड़। सबसे कम: ड्रोन ₹595 करोड़ और IT हार्डवेयर 2.0 ₹908 करोड़।
रोज़गार (परिशिष्ट-I)	सबसे अधिक: खाद्य उत्पाद 3,29,200, बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स 1,69,249 और फ़ार्मा 1,14,880। परिशिष्ट के नोट के अनुसार अप्रत्यक्ष रोज़गार के 5.66 लाख तीन क्षेत्रों (LSEM, IT हार्डवेयर, सौर PV) में रिपोर्ट हुए।

आँकड़ों की जाँच: जो PIB साफ़ नहीं करता

निवेश का योग: हमारी गणना: परिशिष्ट-I के 14 क्षेत्रों का निवेश जोड़ने पर ₹2,40,138 करोड़ आता है, जो परिशिष्ट के कुल से मेल खाता है। हमारे जोड़ के अनुसार सौर PV, फ़ार्मा, ऑटो और विशेष इस्पात मिलकर इसका लगभग 74 प्रतिशत हैं, यानी निवेश कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है।

रोज़गार का मेल: परिशिष्ट-I के रोज़गार का कुल 8,49,069 है, जबकि पाठ में 14.15 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) है। हमारी गणना: 8,49,069 + 5,66,000 = 14,15,069, यानी 14.15 लाख। यह मेल बैठता है, पर इसका अर्थ यह है कि 8.49 लाख में परिशिष्ट के हिसाब से अप्रत्यक्ष रोज़गार शामिल नहीं हैं। विज्ञप्ति यह जोड़ खुद नहीं दिखाती; यह हमारा अनुमान है।

निर्यात की छलाँग: संचयी आँकड़ों से हमारी गणना: वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2.5 लाख करोड़ (6.5 में से 4.0 घटाकर) और 2025-26 में ₹8.7 लाख करोड़ (15.2 में से 6.5 घटाकर) जुड़े, यानी एक वर्ष में लगभग 3.5 गुना। PIB इसे "लगातार वृद्धि" कहता है और